



सूचना दिये प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि प्रार्थी को आवंटन आदेश प्राप्त करने हेतु नोटिस जारी किया गया प्रार्थी आवंटन आदेश प्राप्त करने हेतु सबूतों सहित उपस्थित नहीं आने के कारण प्रार्थी का आवंटन खारिज किया जाता है।

इस संबंध में अपीलांत को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांत ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही यह कथन किया गया था कि आवेदित रकबा आज दिनांक को भी शुद्ध रूप से आराजीराज दर्ज रिकार्ड है। अपीलांत आज दिनांक को भी वादगत् भूमि के आवंटन हेतु राशि मय ब्याज भुगतान करने को तैयार है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांत को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांत का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।



उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांत ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18-12-2003 के विरुद्ध अपील दिनांक 07-06-19 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांत का आवंटन प्रार्थना पत्र सबूतों सहित उपस्थित नहीं आने के कारण खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांत किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 18-12-2003 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 07-06-2003 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके

अध्यक्ष अपील अधिकारी  
बीकानेर

खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में अपीलांट ने आवंटन अधिकारी के समक्ष बतौर भूमिहीन आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते उपनिवेशन तहसील कोलायत के चक 15-16 बीएसडी के मुरब्बा नम्बर 48/34 के किला नम्बर 1 ता 5, 7 ता 13, 19 में 12 बीघा 14 बिस्वा कमाण्ड व किला नम्बर 20 व 21 में 1 बीघा 14 बिस्वा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 14 बीघा 08 बिस्वा भूमि आवंटन की मांग की गई थी। आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट के भूमिहीन आवंटन के प्रार्थना पत्र अपीलांट को वादगत् भूमि के आवंटन का पात्र घोषित करने के पश्चात् अपीलांट का आवंटन, सबूत पेश नहीं करने व आवंटन आदेश प्राप्त करने उपस्थित नहीं आने के कारण निरस्त कर दिया गया।

इसके विपरीत अपीलांट का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। यदि किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी भी किया गया है तो विधिवत रूप से उसकी तामील अपीलांट को नहीं करवाई गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।



इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट को नोटिस जारी पर पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 26-02-2003 को व दिनांक 25-08-2003 को नोटिस जारी करते हुए पन्द्रह दिवस में उपस्थित होने के लिये पाबन्द किया गया। पत्रावली में उक्त नोटिस की विधिवत तामीली का कोई सबूत पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। उक्त नोटिस अपीलांट के रहवास गारबदेसर तहसील लूणकरनसर के पते पर जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में इतनी कम अवधि में नोटिस की तामील होना व राशि की व्यवस्था कर तहसील कोलायत में उपस्थित होना, अपीलांट के सम्भव होना प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को किसी प्रकार की सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये आदेश जैर अपील पारित किया गया है।


अद  
राज्य अपील अधिकारी  
बीकानेर

अभिभाषक अपीलांट द्वारा कथन किया गया है कि अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि आज दिनांक तक अन्य किसी व्यक्ति को आवंटित नहीं है तथा राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज भूमि है तथा वह बकाया राशि जमा करवाने को तैयार है।

7. अतः अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 18-12-2003 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बज्जू/कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादगत् भूमि अन्य को आवंटित नहीं होने पर अथवा अन्य किसी कार्य के लिए आरक्षित नहीं होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 28-02-2020 को सरे इजलास सुनाया गया।



  
(राम कृष्ण सायनी)  
राजस्व अपील अधिकारी  
राजस्व बीकानेर प्राधिकारी  
बीकानेर

